राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 19386/2023

दीनदयाल प्रजापत पुत्र स्वर्गीय जोधाराम, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी सी-39, धाम नगर, सैनिक गेस्ट हाउस के सामने, बाड़मेर वर्तमान में अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग, बीकानेर के पद पर कार्यरत हैं।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री दीनदयाल प्रजापत, याचिकाकर्ता
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एस.आर. पालीवाल
श्री बंशी लाल भाटी, एएजी

माननीय श्री न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य **19/02/2024**

1. याचिकाकर्ता ने इस प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि उत्तरदाताओं को उन्हें जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, जालोर (इसके बाद

'फोरम' के रूप में संदर्भित) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर जिला न्यायाधीश को देय वेतन और अन्य परिलब्धियां देने का निर्देश दिया जाए।

2. याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर विचार करने के उद्देश्य से प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2013 (अनुलग्नक - 1) द्वारा पांच साल की अवधि के लिए फोरम के अध्यक्ष के रूप में नामित/नियुक्त किया गया था।

3. उपर्युक्त आदेश के अनुसार, उन्हें जिला न्यायाधीश (51550-1230-58930-1380-63070) के बराबर वेतन मिलना था।

4. अपना पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 19.02.2022 के आदेश (अनुलग्नक-4) के माध्यम से फोरम के अध्यक्ष के रूप में पुनः नामांकित/पुनः नियुक्त किया गया था।

5. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) 2021 (इसके बाद '2021 के नियम' के रूप में संदर्भित) नियमों के नियम 3 (1) (बी) के अनुसार सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को देय वेतन का हकदार है। क्योंकि, एक बार फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने और जिला न्यायाधीश के बराबर वेतन का लाभ उठाने के बाद, उन्हें सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के रूप में माना जाना और तदनुसार वेतन का भुगतान करना आवश्यक है।

6. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 (इसके बाद '2020 के मॉडल नियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार, फोरम का अध्यक्ष जिला न्यायाधीश के बराबर वेतन का हकदार है।

7. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि बाद में हालांकि 2021 के नियमों को शामिल किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों के मामले को कवर करने के लिए कोई शर्त नहीं है और इस प्रकार उनका वेतन किसी भी मामले में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान प्राप्त वेतन से कम नहीं हो सकता है।

8. याचिकाकर्ता ने दो तरह की दलीलें दी हैं. सबसे पहले, एक बार अधिवक्ता के कोटे से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने और जिला न्यायाधीश को देय वेतन प्राप्त करने के बाद, उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश माना जाना चाहिए और इसलिए, 2021 के नियमों के नियम 3 (1) के खंड (बी) के अनुसार सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को देय वेतन याचिकाकर्ता को देय है।

9. दूसरा, वह 2020 के मॉडल नियम (अनुलग्नक-2) के नियम 3 के अनुसार वेतन पाने का हकदार है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा एक और तर्क उठाया गया कि चूंकि दिनांक 19.09.2022 (अनुलग्नक-9) के एक संचार द्वारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सहायक रजिस्ट्रार ने मॉडल नियम, 2020 के नियम 3 के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने की सिफारिश की है और इसलिए, राज्य 2020 के मॉडल नियम के नियम 3 के अनुसार वेतन का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

11. याचिकाकर्ता को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

12. इसमें कोई विवाद नहीं है कि जब याचिकाकर्ता को पहली बार नियुक्त किया गया था, तो 2021 के नियम लागू नहीं थे, जिसके कारण याचिकाकर्ता को सरकारी आदेश दिनांक 21.09.2013 के अनुसार वेतन का भुगतान किया गया था। हालाँकि, जब याचिकाकर्ता को 19.02.2022 को फिर से नियुक्त किया गया, तो 2021 के नियम प्रख्यापित किए गए थे।

13. 2021 के नियमों के अवलोकन पर, इस न्यायालय ने पाया कि 2021 के नियमों के नियम 3 (1) (सी) के रूप में एक स्पष्ट शर्त है, जो याचिकाकर्ता के मामले को कवर करती है। 2021 के नियमों के नियम 3 (1) का खंड (सी) इस प्रकार है: -

> "(सी) यदि एक प्रैक्टिसिंग वकील को जिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समेकित वेतन की अनुमति दी जाएगी।"

14. इस संबंध में, अधिसूचना दिनांक 17.01.2022 (अनुलग्नक-6) का संदर्भ देना उचित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि जब एक प्रैक्टिसिंग वकील को जिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह प्रति माह 60,000/- रुपये के समेकित वेतन का हकदार होगा।

15. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसे सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश माना जाए और 2021

के नियमों के नियम 3 (1) के खंड (बी) के अनुसार परिलब्धियों का हकदार माना जाए, गलत है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अपने पहले कार्यकाल के दौरान जिला न्यायाधीश के बराबर वेतन प्राप्त किया है, उसे सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश नहीं माना जा सकता है।

16. याचिकाकर्ता का दूसरा तर्क कि उसे 2020 के मॉडल नियमों द्वारा शासित किया जाना चाहिए, भी खारिज किया जा सकता है। माना जाता है कि जब याचिकाकर्ता को दिनांक 19.02.2022 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था, तो 2021 के नियम लागू किए गए थे, जो स्पष्ट रूप से 2021 के नियमों के नियम 3 के खंड (सी) के तहत याचिकाकर्ता के मामले को कवर करता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये केवल आदर्श नियम हैं; और एक बार जब राज्य सरकार ने 2021 के अपने नियम घोषित कर दिए, तो 2020 के मॉडल नियम लागू नहीं होंगे।

17. जहां तक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा भेजे गए दिनांक 19.09.2022 (अनुलग्नक-9) के संचार पर आधारित याचिकाकर्ता के अंतिम तर्क का संबंध है, यह केवल याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को अग्रेषित करने वाला एक संचार है, कोई रचनात्मक आदेश/सिफारिश नहीं।

18. बहस के दौरान, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति को एक प्रैक्टिसिंग वकील के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करने के उनके अधिकार 2020 के मॉडल नियमों के नियम 11 (2) और 2021 के नियमों द्वारा वर्जित हैं।

19. इस न्यायालय के अनुसार, केवल इसलिए कि सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर उपभोक्ता न्यायालयों के समक्ष प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, न तो यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का एक वकील के रूप में अभ्यास करने का अधिकार पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और न ही एक वकील के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति समाप्त हो सकती है। इसलिए, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसकी नियुक्ति एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के रूप में मानी जानी चाहिए न कि प्रैक्टिस करने वाले वकील के रूप में, कम से कम यह कहना गलत है।

20. यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता 2021 के नियमों के नियम 3(1) के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 17.01.2022 की अधिसूचना के अनुसार 60,000/- रुपये प्रति माह के समेकित वेतन का हकदार है, रिट याचिका खारिज की जाती है ।

21. यदि याचिकाकर्ता को दिनांक 17.01.2022 की अधिसूचना के अनुसार कानून के अनुसार परिलब्धियों का भुगतान नहीं किया गया है, तो राज्य इसका शीघ्र भुगतान करेगा।

22. रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

23. स्थगन आवेदन भी तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(दिनेश मेहता**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।